



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (अलाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 18 अप्रैल, 2001/28 चैत्र, 1923

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 18 अप्रैल, 2001

संख्या 1-29/2001-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत "हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2001 (2001 ई.) का

विधेयक संख्यांक-6)" जो आज दिनांक 18 अप्रैल, 2001 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,
सचिव।

2001 का विधेयक संख्यांक 6.

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2001

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2001 है । संक्षिप्त नाम ।
2. हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उप-धारा (3) और (4) में "नगरपालिका समिति" शब्दों के स्थान पर "नगरपालिक परिषद् या नगर पंचायत" शब्द रखे जाएंगे । धारा 10 का संशोधन ।
3. मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 30-क का अन्तः स्थापन ।

"30-क. फार्म-गृहों (हाऊस) का सन्निर्माण.—धारा 30 में किमी व्रत के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई व्यक्ति या उसका उत्तराधिकारी जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ से भूमि का स्वामी है और तत्पश्चात् निरन्तर स्वामित्व रखता है तथा कृषि प्रयोजनों के लिए फार्म-गृह (हाऊस) का सन्निर्माण करने का आशय रखता है, निदेशक को, उसकी अनुज्ञा लेने हेतु साधारण आवेदन करेगा :

परन्तु यह कि फार्म-गृह (हाऊस)—

 - (i) दो सौ वर्ग मीटर से अनधिक निमित क्षेत्र में समाविष्ट है ; और
 - (ii) दो से अधिक मंजिले नहीं है ।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजन के लिए पद "फार्म गृह (हाऊस)" में "पशुशाला" सम्मिलित होगी ।"

परन्तु यह और कि फार्म गृह (हाऊस) के सभी और न्यूनतम दो मीटर का सैट बैंक रखा जाएगा और इसे किसी अन्य उपयोग में नहीं लाया जाएगा ।"
4. मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा 31-क अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा-31-क का अन्तः स्थापन ।

"31-क. संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण-पत्र.—आवेदक, इमारत का उपयोग करने से पूर्व विहित रीति में इमारत का संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा ।"

धारा 39 का
संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 39 में,—

(क) उप-धारा (1) में “एक मास से अन्यून और तीन मास से अनधिक ऐसी अवधि” के भीतर जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए” शब्दों के स्थान पर “पन्द्रह दिन के भीतर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) ऐसे नोटिस से व्यथित कोई व्यक्ति, नोटिस की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर, धारा 39-ग के अधीन अपराधों के शमन के लिए आवेदन करेगा और उस समय तक जब तक कि आवेदन निपटारा जाता है, नोटिस प्रत्याहृत (वापस) हो जाएगा ।” ; और

(ग) उप-धारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(5) यदि अपराध का शमन किया जाता है, तो नोटिस प्रत्याहृत (वापस) हो जाएगा, किन्तु यदि अपराध का शमन नहीं किया जाता है तो नोटिस बना रहेगा, या यदि ऐसे अपराध का भागतः शमन किया जाता है, तो उस विस्तार तक, जिस तक अपराध का शमन किया जाता है, नोटिस प्रत्याहृत (वापस) हो जाएगा, किन्तु उस अपराध के बारे में बना रहेगा जिसका शमन नहीं किया जाता है तथा तदुपरि स्वामी से, शमनित न किए गए अपराध के विषय में, उप-धारा (1) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट पग उठाने की अपेक्षा की जाएगी” ।

धारा 66 का
संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (4) में “हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968” शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर, “हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994” शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे, और “नगरपालिका समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति या पंचायत” शब्दों और चिन्हों के स्थान पर, “नगरपालिक परिषद्, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

धारा 70 का
संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 70 के खण्ड (v) और (vi) में “1968” अंकों के स्थान पर “1994” अंक रखे जाएंगे ।

धारा 71 का
संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 71 के खण्ड (ग) में “हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1968 का 19) के अधीन नगरपालिका समिति की है” शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर “हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अधीन परिषद् की है,” शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 77 का
संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 77 में, उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यदि नगर निगम, नगरपालिक परिषद् या नगर पंचायत को शक्तियां प्रत्या-
दोजित की जाती हैं तो सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्राधिकारियों को, उनके द्वारा

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 1978 के उपबन्धों के अधीन स्थानीय निधि के रूप में संगृहीत फीस का उपयोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी।”।

10. मूल अधिनियम की धारा 83 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 83-क
का अन्तः
स्थापन।

“83-क.—विद्युत, पानी या मलवाही कनेक्शन की अनुज्ञा पर निर्वहन. किसी भी व्यक्ति को, अधिनियम के अधीन गठित योजना या विशेष क्षेत्र के भीतर, जब तक कोई विद्युत, पानी या मलवाही कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, जब तक कि, ऐसे व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, निदेशक या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त न कर लिया गया हो।”।

11. मूल अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (2) में,—

धारा 87 का
संशोधन।

(क) खण्ड (xi) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(xi-क) प्ररूप जिस में अधिनियम की धारा 31-क के अधीन संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना है ;” ; और

(ख) खण्ड (xiv) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(xiv-क) रीति जिसमें अधिनियम की धारा 39-ग के अधीन आवेदन किया जाएगा और अपराध के शमन के लिए प्रभावित की जाने वाली रकम ;”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994. हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की अधिनियमिति के कारण हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 में नगरपालिका समिति तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति की नामपद्धति बदल कर नगरपालिक परिषद् और नगर पंचायत करने के साथ-साथ वर्ष, "1968" को वर्ष "1994" से प्रतिस्थापित करने हेतु कनिष्ठ संशोधन करने आवश्यक हो गए हैं। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 30-क साधारण आवेदन पर अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, फार्म गृह (हाऊस) का निर्माण करने का उपबन्ध करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि फार्म गृह (हाऊस) का निर्माण योजनाबद्ध रीति में किया गया है सैट बैक्स के लिए उपबन्ध बनाने का विनिश्चय किया गया है। हाल ही में 26 जनवरी, 2001 के भूकम्प के पश्चात्, इमारत का उपयोग करने से पूर्व इसकी संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है। अतः इमारत की संरचनात्मक स्थिरता के बारे में नए उपबन्ध जोड़े जा रहे हैं। अपराधों के शमन के बारे में धारा 39-ग के अन्तःस्थापन के पश्चात्, अधिनियम की धारा 39(3) के अधीन प्रतिधारण के उपबन्धों में संशोधन किया जाना अपेक्षित हो गया है। एकल खिड़की पद्धति बनाने समय निदेशक, नगर और ग्राम योजना की शक्तियां शहरी स्थानीय निकाय के पक्ष में प्रत्यायोजित की गई हैं जबकि उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 1978 के अधीन संगृहीत फीस अभी राजकोष में जमा की जानी अपेक्षित है। ऐसे शहरी स्थानीय निकायों को, उक्त रकम का उनकी स्थानीय निधि के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा करने के लिए इस विस्तार तक उपबन्ध किया जा रहा है।

राज्य में अनधिकृत निर्माण के संकट (संबास) पर पूरी (विस्तीर्ण) रोक सुनिश्चित करने के लिए यह विनिश्चित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति, जिसने अनधिकृत निर्माण किया है, के पक्ष में विद्युत, पानी या मल निकास कनेक्शन न दिया जाए। इसलिए यह प्रस्तावित है कि ऐसा कनेक्शन, यथास्थिति, निदेशक या विशेष क्षेत्र विवास प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही दिया जाएगा।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

हरि नारायण सिंह,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला

.....2001.

वित्तीय जापन

—अन्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी जापन

विधेयक के खण्ड 4 और 11 राज्य सरकार को, इमारतों की संरचनात्मक स्थिरता और रीति जिसमें कि धारा 39-ग के अधीन अपराधों के शमन के लिए आवेदन किया जाएगा तथा प्रभारित की जाने वाली रकम के बारे में नियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं।

यह प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2001

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

हरि नारायण सिंह,
प्रभागी मन्त्री।

रामेश्वर शर्मा,
सचिव (विधि)।

स्थान:

..... 2001.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY
PLANNING (AMENDMENT) BILL, 2001
 (AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A
 BILL

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977)

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-second Year of the Republic of India, as follows :—

Short title 1. This Act may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 2001.

Amendment of section 10. 2. In section 10 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-sections (3) and (4), for the words "Municipal Committee", the words "Municipal Council or Nagar Panchayat" shall be substituted.

(12 of 1977)

Amendment of section 30-A. 3. In section 30-A of the principal Act, after the existing proviso, the following shall be added, namely :—
 "Provided further that minimum two metre set backs shall be kept on all sides of the farm house and shall not be put to any other use."

Insertion of section 31-A. 4. After section 31 of the principal Act, the following new section 31-A shall be inserted, namely :—

"31-A. Structural Stability Certificate.—

The applicant shall submit a Structural Stability Certificate of the building before putting the same into use, in the manner prescribed."

Amendment of section 39.

5. In section 39 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "such period being not less than one month and not exceeding three months as may be specified therein", the words "fifteen days" shall be substituted;

(b) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) Any person aggrieved by such notice may within fifteen days of the receipt of the notice, apply for composition of offences under section 39-C and till the time the application is disposed of, the notice shall stand withdrawn." ; and

(c) for sub-section (5), the following shall be substituted, namely :—

"(5) If the offence is compounded, the notice shall stand withdrawn, but if the offence is not compounded, the notice shall stand, or if such offence is partly compounded, the notice shall stand withdrawn to the extent the offence is compounded, but shall

stand in respect of the offence which is not compounded, and thereupon the owner shall be required to take steps specified in the notice under sub-section (1) in respect of the offence not compounded.”.

6. In section 66 of the Principal Act, in sub-section (4), for the words, signs and figures “Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 and the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968” the words, signs and figures “the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994” shall be substituted, and for the words and signs “Municipal Committee, Notified Area Committee or a Panchayat” the words and sign “Municipal Council, Nagar Panchayat or a Gram Panchayat” shall be substituted.

Amendment
of section
66.

7. In section 70 of the principal Act, in clauses (v) and (vi), for the figures “1968”, the figures “1994” shall be substituted.

Amendment
of section
70.

8. In section 71 of the principal Act, in clause (c), for the words, signs and figure “Committee has under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968”, the words, sign and figure “Council has under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994” shall be substituted.

Amendment
of section
71.

9. In section 77 of the principal Act, after sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely :—

Amendment
of section
77.

“Provided that in case the powers are delegated to Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchayat, the Government may, by notification, permit such authorities to utilise the fee collected under the provisions of Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 1978, toward their local fund.”.

10. After section 83 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely :—

Insertion
of section
83-A.

“83-A. *Restriction on grant of Electricity, Water or Sewerage connection.*—No electricity, water or sewerage connection shall be given to any person within the Planning or Special Area constituted under the Act, unless a No Objection Certificate has been obtained by such person from the Director or the Special Area Development Authority, as the case may be.”.

11. In section 87 of the principal Act, in sub-section (2),—

Amendment
of section
87.

(a) after clause (xi), the following new clause shall be inserted, namely :—

“(xi-a) the Form in which Structural Stability Certificate is to be furnished under section 31-A of the Act;” ; and

(b) after clause (xiv), the following new clause shall be inserted, namely :—

“(xiv-a) the manner in which an application shall be made under section 39-C of the Act and the amount to be charged for composition of offence;”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The enactment of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 have necessitated certain amendments in the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 to change the nomenclature of Municipal Committee and Notified Area Committee to that of Municipal Council and Nagar Panchayat as well to substitute the year, "1968" with "1994". Section 30-A of the Act *ibid* provides for construction of a farm house after obtaining permission on a simple application. In order to ensure that the farm house is constructed in a planned manner, it has been decided to make a provision of set backs. After the recent Earthquake of 26th January, 2001, the structural stability of building is required to be ensured before putting the same into use. As such, a new provision regarding the structural stability of the building is being added. After insertion of section 39-C regarding composition of offences, the provisions of retention under section 39 (3) of the Act is required to be amended. While creating single window system, powers of the Director, Town and Country Planning are delegated in favour of the Urban Local Bodies, whereas the fee collected by them under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 1978 is still required to be deposited in the Government Treasury. To allow such Urban Local Bodies to utilise the said amount towards their local fund, a provision to that extent is being made.

To ensure a greater check on the menace of unauthorised construction in the State, it has been decided that no electric, water or sewerage connection be released in favour of any person who has carried out unauthorised construction. As such, it is proposed that such connection shall be given only after obtaining a No Objection Certificate from the Director or the Special Area Development Authority, as the case may be.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

HARI NARAIN SINGH,
Minister-in-charge.

SHIMLA :

The.....2001.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 4 and 11 of the Bill seek to empower the State Government to make rules regarding the structural stability of the buildings and the manner in which the application for composition of offence under section 39-C shall be made and the amount to be charged. This delegation of power is essential and normal in character.

**THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING
(AMENDMENT) BILL, 2001**

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977)

HARI NARAIN SINGH,
Minister-in-Charge.

RAMESHWAR SHARMA,
Secretary (Law).

SHIMLA :
The.....2001.

